



04 - बिहार चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आगे क्या ?



05 - अकेलेपन के कवि निर्मल वर्मा

A Daily News Magazine

गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025



गोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 203, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - विद्यार्थी एक अच्छे इंसान जरूर बने : कलेक्टर



07 - बाग प्रिट केवल एक हस्तशिल्प नहीं, यह संस्कृति, परंपरा और...



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsaverenews



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

अतिम यात्रा पर निकले पिता
ऑगन में कितनी जगह रह जाते हैं,

खाट के नीचे चप्पल और छड़ी में
बैठक के रेंडियो और जेब घड़ी में
टैंगी टोपी और सख्ती की थड़ी में,

कितना कुछ हरा है
घर के बाहर लिखे छोटे नाम में
कितना कुछ भरा है,

सब ठीक है मैं गले रुकूँते हैं
अम्मा के फोन अवसर कटते हैं ।

- अंजना टंडन

खंडवा में जैन मुनि को आयशर वाहन ने रौंदा, मौत

इंदौर हाईवे पर हादसा

खंडवा (नप्र)। खंडवा में इंदौर-ऐदलाबाद नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में जैन मुनि गजेंद्र मुनि महाराज की मौत हो गई। वे नामपुर से पैदल विहार करते हुए इंदौर जा रहे थे, उनके साथ दो अन्य जैन मुनि भी थे। रास्ते में ग्राम मोकलावा टोल टैक्स के पास एक तेज रफतार आयशर वाहन ने उन्हें रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। आयशर वाहन की टक्कर इतनी तेज थी कि जैन मुनि की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया।



सीसीटीवी फुटेज में दिखा वाहन, तलाश जारी- टीआई दिल्ली देवड़ा ने बताया कि टोल टैक्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक आयशर वाहन हादसे के समय गुजरता दिखा। पुलिस वाहन और ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम पंधाना में कराया, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने शिल्पिया गांव के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। जैन समाज के लोगों ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से मांग की कि आरोपी वाहन चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रसंगवश

सौतिक बिस्वास

अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद भी भारत शायद ही उससे मक्का खरीदे। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉबर्ड लुटनिक ने हाल ही में भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए यह सवाल उठाया था। उन्होंने भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर भी प्रश्न उठाया था। लुटनिक ने एक साक्षात्कार में भारत पर अमेरिकी कृषि उत्पादों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत से कृषि बाजार को खोलने का भी अनुरोध किया।

अमेरिका दो अप्रैल से रेंसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर में कृषि एक बड़ा मसला बनने जा रहा है। टैरिफ अन्य देशों से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। ट्रंप ने बार-बार भारत को 'टैरिफ किंग' और व्यापार संबंधों का 'दुरुपयोग' करने वाला देश करार दिया है।

अमेरिका कई सालों से भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने के लिए दबाव बना रहा है। वो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। जो देश कभी खाद्यान की कमी से जूझता था वो अब अनाज लेकर फल तक एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत को अब मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी बन गया है। बागवानी और मुर्गीपालन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। भारत आज न केवल अपने देश के 1.4 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि विश्व का आठवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक है। भारत

दुनिया भर में अनाज, फल और डेयरी प्रोडक्ट्स भी भेज रहा है। कृषि में इस सफलता के बाद भी भारत उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और बाजार में पहुंच के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। दुनिया में दामों के उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और भी बढ़ा देते हैं। भारत में फसल की पैदावार भी वैश्विक स्तर पर सबसे कम है।

छोटी जोत इस समस्या को और भी बदतर बना देती है। भारत में खेती से देश की आधी आबादी करीब 70 करोड़ लोगों का भरण पोषण हो रहा है। यह भारत की रीढ़ बनी हुई है। खेती भारत के करीब आधे कामगारों को रोजगार देती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका केवल 15 फीसदी योगदान है। वहीं अमेरिका की दो फीसदी से कम आबादी खेती पर निर्भर है।

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में सीमित नीकरियों के कारण कम वेतन पाने वाले अधिक लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। कृषि सरप्लस यानी अधिशेष के बावजूद भी भारत अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर शुल्क से 150 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला औसत टैरिफ 37.7 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3 प्रतिशत है।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार मात्र 800 करोड़ रुपए का है। भारत मुख्य रूप से चावल, जौ, गन्ना, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है, जबकि अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है।

दोनों देश एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं।

वक्फ संशोधन बिल 2024

वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए : शाह

एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक

स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार

का कानून, मानना पड़ेगा

नईदिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 'वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, क्या धक्का दे रहे हों भाई। संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल पर देर रात तक बहस जारी थी।

उन्होंने कहा- वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनोरिटीज को खराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है अल्लाह

के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है, जिस पर हमारा हक है। शाह ने कहा- जहाँ तक भारत का सवाल है। आजादी के बाद इसे बदला गया। ये पूरा झगड़ा 1995 से चल रहा है। ये पूरा झगड़ा वक्फ में दखल का है। सुबह से जो चर्चा चल रही है। उसे मैंने बारीकी से सुना है। ढेर सारी भातियाँ सदस्यों में हैं। कई भातियां देश में फैलाई जा रही हैं। शाह ने कहा- 2013 में वक्फ के जो अमेंडमेंट आए, वो न किया होता तो ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2014 में चुनाव आने वाला था, 2013 में रातोंरात तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानूनों को बदला गया था। इसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 VVIP संपत्ति कांग्रेस सरकार ने वक्फ को देने का काम किया। शाह ने कहा- जमीन किसकी इसकी जांच कलेक्टर करेगा

शाह ने पूछ- एक बात बताओ, मंदिर के लिए



जमीन खरीदनी है तो मालिक कौन होगा, ये कौन तय करेगा, कलेक्टर ही तय करेगा। वक्फ की जमीन किसकी है, यह जांच कलेक्टर करे तो आपत्ति क्या है। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे हैं, सरकारी संपत्ति पर नहीं बने हैं। वक्फ की भूमि सरकारी है या नहीं, ये कलेक्टर जांच करेगा। शाह ने कहा- भाजपा का सिद्धांत स्पष्ट है कि हम वोट बैंक के लिए कानून नहीं लाएँगे। कानून न्याय के लिए होता है। ये बोलें कि कैसे कैसे कानून ला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया। ये कानून इसी (मोदी सरकार) सरकार में आया। गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, बिजली और घर दिए गए।

कानून भारत सरकार का है, इसे मानना होगा- शाह ने कहा- आपके (विपक्ष) हिस्साब से चर्चा नहीं होगी। इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है। किसी परिवार की नहीं चलती है, जनता के मुमूड़े हैं और चुनकर आए हैं। कोई भी फैसला देश की अदालत की पहुँच से बाहर नहीं रखा जा सकता। जिसकी जमीन हड़प ली गई वो कहाँ जाएगा। आपने अपने फायदे के लिए किया था और हम खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने रेवेन्यू का मामला कम कर दिया। 7 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया। ये गलत समझ रहे हैं, ये पैसा वक्फ के काम आएगा। कोई मॉस्जिद बन रही है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। आदिवासियों, ASI, निजी

संपत्ति सुरक्षित होगा। वक्फ करने के लिए स्वामित्व होना जरूरी है। पारदर्शिता के लिए सूचना की प्रक्रिया को अपनाना होगा। नए वक्फ पारदर्शी रूप से रजिस्टर्ड कराने होंगे।

कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम किया

अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर बनाने की बात आई, तो कहा गया कि खून की नदियां बह जाएंगी, मुसलमान सड़क पर उतर आएगा। ट्रिपल तलाक, CAA के केस में ऐसा कहा गया कि मुसलमान की नागरिकता जाएगी। अगर 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई हो तो सदन के पटल पर रखे। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर क्या-क्या नहीं कहते थे। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के सीएम हैं, वहां विकास हो रहा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम करके वोट बैंक बनाने का काम किया। (शेष पृष्ठ-2 पर)

अगले तीन वर्ष में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जनप्रतिनिधियों से पूछकर बनाएं गांवों की सड़कें

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की

पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुगम जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके



आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य-योजना बनाई जाए। सड़कों की आवश्यकता के संबंध में विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमत अवश्य लिया जाए। राज्य सरकार अगले तीन वर्ष में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में

उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहते हुए तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नालोजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर उन्नयन और लेन विस्तारिकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पाण्डटोला से बीजाटोला तक देश की

पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है।

सड़कों के संधारण और उन्नयन के लिए भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में प्रदेश, देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्गों के संधारण के लिए वर्ष

● प्रधानमंत्री जन-मन योजना में मध्यप्रदेश ने बनाई देश की पहली सड़क

2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सम्पूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।

बताया गया कि प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 बसाहटों तक रोड़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 4 के अंतर्गत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सामान्य संधारण कार्यों का प्राक़लन तैयार करने और तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति आदि की ऑनलाइन व्यवस्था सव्गे पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।

शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि विक्रम संवत् 2082वर्ष प्रारंभ हुआ है। शिप्रा के किनारे हमने इस नए साल को धूमधाम से मनाया। ब्रह्मध्वज का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने ब्रह्मध्वज की जानकारी देते हुए बताया कि सृष्टिकर्ता महाकाल की प्रेरणा से ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया। 1955885126 वर्ष पूर्व से प्रवर्तित सृष्टिाब्द के आरम्भ से ही कोटि सूर्य को महिमा प्रदान की गयी है। यह ब्रह्मध्वज वर्षों पूर्व परम्परा से श्रीमहाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन के शिखर पर समय-समय पर स्थापित किया जाता रहा है। यह परंपरा फिर शुरू हो गई है।

श्रीमहाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थापित हुआ ब्रह्मध्वज



विक्रमोत्सव

डॉ. जफर महमूद

उज्जैन से

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत् 2082 और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर उज्जैन में माँ क्षिप्रा जी के तट पर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने ब्रह्मध्वज की पूजा अर्चना की। जिसके बाद सर्वप्रथम ब्रह्मध्वज श्रीमहाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया। इसके अलावा उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मध्वज को पूजन के बाद समर्पित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सृष्टि आरम्भ दिवस, वर्ष प्रतिपदा, हिंदू नव वर्ष की

पिछले15 महीनेमें

‘नक्सली’ संगठनों ने टेक दिए घुटने



रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे नक्सल विरोधी अभियान के बाद अब माओवादी संगठन शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। अमित शाह के बख्तर दौर से पहले ही नक्सली संगठन केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है, तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली संगठन द्वारा यह लेटर तेलुगु भाषा में जारी किया गया है। लेटर में 28 मार्च 2024 की तारीख लिखी हुई है। बताया जा रहा है तेलंगाना में नक्सली संगठन की एक अहम बैठक हुई

थी। जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ने और बातचीत करने पर सहमति बनी है। नक्सली संगठनों ने लेटर में कहा है कि युद्धविराम की घोषणा होनी चाहिए। लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता की पहल की थी। नक्सली संगठन द्वारा जारी लेटर में कहा गया है- भाजपा जहां पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें तथा अन्य दलों की राज्य सरकारें उन जनसंघर्षों को मिटाने के लिए पूर्वी और मध्य भारत में युद्ध कर रही हैं। अगर हमारी पार्टी उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति के लिए लड़ रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें उन संघर्षों को दबाने के लिए खुफिया एजेंसियों का उपयोग कर रही हैं।

वक्फ संशोधन बिल---

पेज का शेष

अनुराग ठाकुर बोले- भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए



लिए किया गया, पर चुनाव हार गए।

जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति अपना बताने लगेगा: रिजिजू

रिजिजू ने कहा- अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता, तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर-अधिसूचित हो गई होतीं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला- बिल पास हुआ तो देशभर में आंदोलन करेंगे-ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।

हरसिमरत बोलीं- इनकी मंशा मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की-शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सुबह से ये सोच रही हूं कि जिस पार्टी का तीन टर्म से एक मुस्लिम सांसद नहीं है। एक भी मुस्लिम महिला सांसद नहीं है। जो पार्टी मुस्लिम विरोध की राजनीति करती आई है, उनको कौन सा ईद का चांद दिख गया। जुवान पर दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला है। वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है। इनकी मंशा केवल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की है। उनके पैसों पर कब्जा करने की

है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद बोले- बिल मुस्लिमों के खिलाफ- नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने कहा कि यह जो बिल लाया जा रहा है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। आपने राज्य सरकारों के अधिकारों को छीना है। इस मुल्क पर हमें फख है। ये विशेष तबके के खिलाफ लाया गया है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता के लिए मशहूर है, इस बिल से उस सेकुलरिज्म पर प्रश्नचिह्न लगता है।

केसी वेणुगोपाल बोले- भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा-कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- हमारे यहां भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। रिजिजूजी इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को बोर्ड में ला रहे हैं। वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो किसी को नॉमिनेट कर सकता है। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं। आप वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी धार्मिक है। केरल में देवस्थानम बोर्ड में विधायक किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो विधायक हिंदू होगा। मुस्लिम नहीं होगा। किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन विधायक के पास ये अधिकार नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड के मंबर को चुने।

मोहिबुल्लाह बोले- सरकार दुआ करने से रोक रही-सपा सांसद मोहिबुल्लाह बोले- हम इस बिल का विरोध करते हैं। ये सूफियों-ऋषियों और मुनियों का देश है और आप दुआ करने से रोक रहे हैं। अब इमाम को अपने इमाम होने का सबूत देना होगा। 100 साल पुरानी मस्जिद बाकी है और

600 साल पुरानी मस्जिद का कागज नहीं है तो वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी। क्या है ये बदलाव। इससे क्या संदेश जाएगा।

राम विलास के सांसद बोले- विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता-(राम विलास पासवान) सांसद अरुण भारती ने कहा- इस विधेयक के विरोध में विपक्ष हमेशा धार्मिक पक्ष उठाता रहा है। विपक्ष कहता रहा कि मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी। विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र और प्रायोजित राजनीति की बात खत्म हो जाएगी।

टीएमसी सांसद बोले- वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास-टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा- वक्फ एक धार्मिक और समाजसेवा करने वाला संस्थान है। इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं किया जा सकता है। हिंदू ईंग्लिश कानून फॉलो करते हैं और

मुस्लिम ईंग्लिश लॉ नहीं मानता। यह अंतर है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। मुतवल्ली के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। **अखिलेश का सवाल- क्या डिफेंस-रेलवे की जमीन बेची नहीं जा रही-**अखिलेश ने कहा कि वक्फ पर कारोबार की बात कह रहे हैं। धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। यूपी के मुख्यमंत्री बोले कि कारोबार होगा। 30 की गिनती पर अटक हुए हैं, जैसे तीसमार खां हो। कारोबार का पूछा तो बोले कि 30 गुणा 10 हजार करोड़। कुंभ से कारोबार की बात कर रहे हैं। मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी यह मानता हूं। क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल न करे इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। जिस प्रदेश से मंत्री आते हैं कम से कम यह तो बता दें कि चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं।

वक्फ संशोधन कानून बिल का पूरे देश ने स्वागत किया है: डॉ. सनवर पटेल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वक्फ बोर्ड संसोधन कानून लाया गया है इस संबोधित कानून का देश ईमानदार मुस्लिम समाज ने डोल नगाड़े बजाकर देश की सरकार का अभिनंदन किया है, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने नये बिल का स्वागत करते हुए कहा कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं से मुक्ति मिलेगी, वही गरीब निर्धन मुस्लिम परिवारों के लिए एक नई आशा की किरण जायेगी। डाक्टर पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी अब एक अभियान चला कर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने वाले माफियाओं को जल्दी ही बेदखल किया जायेगा और जरूरत पड़ी तो कानून के माध्यम से जेल भेजा जायेगा। वक्फ की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज के उत्थान और स्वावलंबी बनाने के लिए किया जाएगा , शिक्षा के बड़े संस्थानों से चर्चा कर मुस्लिम समाज के बच्चों को डाक्टर,इंजीनियर, और भारत रत्न अब्दुल कलाम जैसा बनने की ललक जगाई जायेगी। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पटेल ने भोपाल में मुस्लिम समाज द्वारा आज नये बिल के समर्थन और स्वागत किया गया और अभिनंदनीय है, उन्होंने कहा वह स्वयं उन सभी के बीच भिटाईयां लेकर जायेंगे।

एलओसी पर सेना ने 5 घुसपैटिए मार गिराए



श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने 4-5 पाकिस्तानी घुसपैटियों को मार गिराया। हालांकि, इसे लेकर सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। घटना मंगलवार शाम को पुछ में नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड परिया में हुई। एलओसी से सटे इलाके में 3 माइन ब्लास्ट हुए और पाकिस्तान की ओर से फायरिंग भी हुई थी। दावा है कि इसी समय आतंकियों ने घुसपैट की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की थी। जिसमें 4 से 5 घुसपैटियों मारे गए। फायरिंग और ब्लास्ट को लेकर सेना से बात की। सेना ने कहा- एक अप्रैल को एलओसी के उस पार से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैट की कोशिश की।

कुणाल कामरा को तीसरा समन,5 अप्रैल को बुलाया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉना मामले में कॉमिडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने तीसरा समन भेजा है। उन्हें 5 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन में पृष्ठछाछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस कामरा को 2 समन भेज चुकी है। इधर, मंगलवार को कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जरिस्ट सुंदर मोहन ने कामरा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले 28 मार्च को हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक की अग्रिम जमानत दी थी।

देशभर में 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर हुआ अतिक्रमण

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राज्यों द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, जो दिल्ली सिक्किम और गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। पिछले सप्ताह एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। अभी तक 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7506.48 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है। जो दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक है।

सेना, रेलवे नहीं,वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा निजी संपत्ति

● रिजिजू ने संसद में आंकड़ों से बताया वक्फ के पास कितनी संपत्ति

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वक्फ की संपत्ति पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा, वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि रेलवे और सेना की जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका इस्तेमाल देश के लिए होता है। वह किसी की



निजी संपत्ति नहीं है। बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड करीब 8 लाख 70 हजार संपत्तियों को नियंत्रित करता है।

14 दिन बाद साहिल को देखते ही रो पड़ी मुस्कान

● जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मुलाकात ,बढ़ी न्यायिक हिरासत

मेरठ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद साहिल और मुस्कान की बुधवार को 14 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय पेशी के दौरान पहली बार मुलाकात हुई। यह मुलाकात जेल के वीडियो कॉफ्रेंसिंग रूम में हुई, जहां कोर्ट में उनकी ऑनलाइन पेशी कराई गई। जैसे ही मुस्कान ने साहिल को देखा, वह भावुक हो गई और रो पड़ी। हालांकि जेल प्रशासन ने उन्हें एक-दूसरे से बात नहीं करने दी। साहिल और मुस्कान की



न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।

जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी गिरफ्तार

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आतंकवादी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दरअसल, 30 मार्च 2022 को राजस्थान के निंबाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स के साथ तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें जुबेर पिता फकीर मोहम्मद, अल्लमस खान और सरफुद्दीन उर्फ सेफुल्ला थे। यह सभी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए कार से आरडीएक्स ले जा रहे थे। इन्होंने साजिश में शामिल 11 आतंकियों के नाम बताए थे। फरार आतंकी फिरोज की तलाश के लिए पूर्व रहे हैं, दुनिया की सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है तो हमारे देश का मुसलमान गरीब क्यों है।

यूपी के 50 जिलों में फ्लैग-मार्च पुलिस की छुट्टियां भी कैसिल

● वक्फ बिल पर इमरान मसूद बोले-मैं भी राम का वंशज,ट्रस्ट में शामिल कराइए

लखनऊ (एजेंसी)। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।



कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। संसद के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- भाजपा ने रेलवे को बेचा,

डिफेंस की जमीन बेची और अब वक्फ की जमीनें बेची जाएंगी। उन्होंने कहा- जिन लोगों के लिए यह बिल लाया जा रहा है, उनकी ही बातों को अहमियत ना देना, इससे बड़ी नाइसाम्मी क्या होगी।

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैं भी राम का वंशज हूं। मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करवा दें। 78 फीसदी वक्फ की संपत्ति विवादामुद्द घोषित कर देना यूपी तरह से गलत है। वहीं, इससे पहले यूपी सरकार ने पुलिस की छुट्टियां कैसिल कर दी है। जिन पुलिसकर्मियों की छुट्टियां मंजूर थीं, वो भी रद्द हैं।

● मां बोली-बेटे की तेरहवीं के लिए कमाने गुजरात गए थे,लेकिन सब खत्म हो गया

हरदा (एजेंसी)। होली पर बेटे सत्यनारायण का निधन हो गया था। उसकी तेरहवीं करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पोते समेत परिवार के 11 लोग काम करने गुजरात गए थे। वहां से काम करके लौटते तो बेटे की तेरहवीं करती, लेकिन उसके पहले ही पूरा परिवार खत्म हो गया। गुजरात से पता चला है कि हमारे घर के जो भी लोग काम करने गए थे, सभी शांत हो गए हैं। इसमें बेटा-बेटी, पोते-पोतियां, भांजे-भाजियां भी शामिल हैं। ये दर्द है गीताबाई का। हरदा के हंडिया की रहने वाली गीताबाई के तीन पोते समेत परिवार के 11 लोग गुजरात के बनासकांठ के पास बीजा पटाखा में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर में



विस्फोट में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। इनमें विष्णु (22), राजेश (25) और बिट्टू (15) तीन सगे भाई थे। इस हादसे में अब तक 20 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 18 की पहचान हो गई है।

इनमें से 8 शव हरदा के परिवार के जबकि 10 देवास जिले के हैं। दो शव ज्यादा जिले हैं जिनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये हरदा के ही हैं। पहले इसे हादसे में 21 मजदूरों की मौत की बात सामने आई थी। 8 मजदूरों का इलाज चल रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर है। हरदा परिवार का एक सदस्य लापता है। जिस समय हादसा हुआ, उस दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे।

परिजन बोले-

अच्छी मजदूरी की उम्मीद में गए थे गुजरात- हादसे में घायल विजय के भाई वीरेंद्र कावरे ने बताया कि कोलीपुरा टप्पर में रहने वाली लक्ष्मीबाई सभी को घर लेने आई थीं। इसके बाद सभी गुजरात काम करने गए थे। वह पहले भी कोलीपुरा में पटाखा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लॉस्ट के बाद जिले की सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं। कुछ दिनों पहले लक्ष्मी बाई उन्हें अच्छी मजदूरी मिलने की बात कहकर अपने साथ गुजरात ले गई थीं। भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका गुजरात के अस्पताल में उपचार जारी है।

पूर्व जेल डीआईजी की पत्नी-भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस

भोपाल (नप्र)।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल ऑफिस ने दिवंगत जेल डीआईजी उमेश कुमार गांधी की पत्नी अर्चना गांधी और उनके भाई अजय कुमार गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह मामला 29 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत में दर्ज किया गया।



ईडी ने 3 जनवरी को इनकी संपत्तियों को जब्त किया था।इनमें सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियां (जमीन, मकान आदि) और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।

भोपाल में न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिए जाने पर ईडी ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच की थी।लोकायुक्त पुलिस ने उमेश कुमार गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी आय से कहीं ज्यादा थी। इसी के आधार पर ईडी ने आगे जांच की।

तीन जनवरी को कुर्क की थी ईडी ने संपत्तियां- ईडी ने पाया कि उमेश कुमार गांधी ने अपने परिवार और करीबी लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में चल- अचल संपत्तियां खरीदी थीं।कुल 4.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं।इनमें जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और किसान विकास पत्र शामिल हैं।

ईडी ने 3 जनवरी 2025 को इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है।

55 लाख बेस प्राइज, मिले सवा करोड़

भोपाल (नप्र)।भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के जिन प्लॉट्स का बेस प्राइज 55 लाख रुपए था, उसके सवा करोड़ रुपए मिले हैं। अयोध्या नगर में यह प्लॉट्स दोगुने रेट पर बिके।ऑनलाइन बिड डाली गई थी, जिसमें यह राशि हाउसिंग बोर्ड की झोली में आई।

अयोध्या नगर एक्सटेंशन में हाउसिंग बोर्ड को अपने प्लॉट्स की नीलामी में खासा फायदा हुआ है।54.72 लाख रुपए बेस प्राइज वाले प्लॉट्स सवा करोड़ में बिके हैं।होली के पहले बोर्ड ने अपने अयोध्या एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में बचे हुए 11 प्लॉट्स को ऑफर के माध्यम से बेचने के लिए पहल की गई थी।इसकी बोली एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डाली गई थी।

इन प्लॉट्स की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि 11 प्रॉपर्टी के बदले 200 से ज्यादा आवेदन आए।बोर्ड ने 1800 स्कैयर फीट के 3 प्लॉट्स का बेस प्राइज 54.72 लाख रुपए रखा था।इसमें एक प्लॉट 1.25 करोड़, दूसरा 1.21 करोड़ और तीसरा 1.18 करोड़ रुपए में बिका।

1500 स्कैयर फीट वाले 45 लाख रुपए बेस प्राइज वाले प्लाट 60 लाख रुपए से ज्यादा में बिके।

कलेक्टर गाइड लाइन के मुकाबले बोर्ड को 77 प्रतिशत ज्यादा का रेट मिला

बोर्ड को 5.37 करोड़ रुपए की बेस प्राइज के अगेंस्ट नीलामी में 8.72 करोड़ रुपए मिले।यह बेस प्राइज से 62 फीसदी अधिक है।बोर्ड ने लगभग 3 हजार रुपए स्कैयर फीट का बेस प्राइज रखा हुआ था।ज्यादातर प्लॉट्स के लिए 4 हजार रुपए से लेकर 6500 रुपए तक ज्यादा की बोली लगाई गई।

दो और प्रोजेक्ट में भी चल रही बुकिंग- हाउसिंग बोर्ड के डिटी हाउसिंग कमिशनर एमके साहू ने बताया, अयोध्या बायपास के 10 लेन होने के प्रस्ताव से इस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लगे हैं।हाइवे के ठीक किनारे हमारे दो और प्रोजेक्ट सुरक्ष परिसर और लवकुश हाइट्स में भी बुकिंग चल रही है।जल्द ही हम अयोध्या में दो और बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने वाले हैं।

शराब दुकान के विरोध में सुंदरकांड

सेमरा में भी प्रदर्शन; स्कूली बच्चे- महिलाएं भी मैदान में उतरे

भोपाल (नप्र)।भोपाल के अवधपुरी में ऋषिपुरम तिराहे के साथ अब सेमरा साईराम कॉलोनी में भी शराब दुकान खुलने का विरोध तेज हो गया है।यहां बुधवार सुबह 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया।ताकि, दुकान दूसरी जनह शिफ्ट हो सके।

रहवासियों का कहना है कि अभी जिस जगह दुकान है, वहां स्कूल-धार्मिक स्थल के साथ रहवासी इलाका भी



है।ऐसे में हर रोज़ रोक रहवासी परेशान हो रहे हैं।इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए।

कलाली बंद कराने के लिए स्कूल बच्चे और महिलाएं भी मैदान में उतर गई हैं।बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर इलाके में रैली भी निकाली और दुकान के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन कर रहे जीतू मलोटिया ने बताया कि स्टेशन रोड स्थित साईराम कॉलोनी सेमरा गेट मुख्य मार्ग पर शराब दुकान है।

भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी

मुस्लिम महिलाओं ने कहा- थैंक्यू मोदीजी

भोपाल (नप्र)। संसद में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। भोपाल में इसके समर्थन में कुछ मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। आनंदनगर और कोकता इलाके में बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाएं हाथों में गुलाब थामे थीं। वे ‘थैंक्यू, मोदी जी’ और ‘वी सपोर्ट मोदी जी’ लिखी तख्तियां लिए थीं। भोपाल के हथई खेड़ा डैम के पास भी जश्न मनाया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम बताया।

विधायक आरिफ मसूद ने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि कलेक्टर को जिम्मेदार बनाया जा रहा है। वही कलेक्टर जिसने हमारे कब्रिस्तानों को सरकारी घोषित किया हुआ है। हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमारे पास 1959 के 41 और 1947 के दस्तावेज हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है, लेकिन कलेक्टर इसे सरकारी संपत्ति बता रहा है।

संपत्ति सही हाथों में होना चाहिए- विधायक रामेश्वर- हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने



कहा- इस संपत्ति का सही लेखा-जोखा किसके पास है? यह संपत्ति सही हाथों में होनी चाहिए ताकि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए इसका उपयोग कर सके। विधायक

शर्मा ने कहा हम गरीबी में रहने वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते। अगर मुसलमान गरीब रहेगा तो उसकी जिंदगी पंचर की दुकान पर ही गुजर जाएगी। ऐसे में हम कैसे कह सकते

हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचा है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ गुंडे-बदमाशों के बारे में सोचा है।

यह बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं : मंत्री सारंग

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, भोपाल में जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने बिल के समर्थन में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, वह अनर्गल प्रचार करने वाले नेताओं पर करारा तमाचा है। यह बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं है और भोपाल में मुस्लिम भाइयों-बहनो ने अपना समर्थन देकर इसे साबित कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल जो भी पढ़ेगा, वह इसका विरोध नहीं करेगा।

उज्जैन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प

सीएम का पुतला फूंक रहे थे; प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर सरपंच को पीटने का आरोप

उज्जैन (नप्र)। आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत का विरोध और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने उज्जैन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव का पुतला जलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई।

आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सरपंच जीवन मालवीय की पिटाई कर दी। घायल सरपंच जीवन मालवीय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की।सौरभ शर्मा मामले में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी को जमानत मिलना, इसमें सरकार की मिलीभगत दिखाई देती है।

पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प- बता दें कि भोपाल में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथियों को जमानत मिल गई है। लोकायुक्त ने कोर्ट में अब तक उनके खिलाफ चार्ज शीट पेश नहीं की है। आरोपियों को जमानत मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए आव्हान पर बुधवार दोपहर को उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा और सीएम का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी आपस में भीड़ गए।



कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बेरिकेडिंग कर सभी ओर से रास्ते बंद कर दिए थे। एक फायर फाइटर समेत फायर ईस्टिंगिशर और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एंड्रशनल एसपी नीतेश भार्गव ने कहा,कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सामग्री

नीचे फेंकी गई। ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया गया। सभी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

प्रदर्शन में कांग्रेस समर्थित सरपंच की पिटाई

कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौहान, ललित मीणा सहित कांग्रेस के अन्य नेता की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस बीच उन्हेल के पास बड़लाई के सरपंच जीवन मालवीय पुतला लेकर पहुंचे और उन्होंने उसमे आग लगा दी।पुलिस ने पुतला

छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुतले में आग लग चुकी थी। हालांकि पुलिस ने उसे पूरा जलने नहीं दिया। इस बीच पुतला छीन रही पुलिस ने सरपंच को जमकर पीट दिया। सरपंच को पीटता देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस से बचाया।

सरकार पर भ्रष्टाचारी को संरक्षण का आरोप

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में जिस तरह से परिवहन घोटाला हुआ है, उसमें लोकायुक्त और शासन ने सरकार का पक्ष तक नहीं रखा। इसमें तत्कालीन मंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक सभी शामिल हैं। सौरभ शर्मा को जमानत क्यों मिल गई, जबकि एक तरफ किलो में सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुए। लोकायुक्त और भाजपा सरकार सौरभ शर्मा को संरक्षण दे रही है। विपक्ष पूरे प्रदेश में इस मिलीभगत के खिलाफ प्रदर्शन कर इसे उजागर कर रहा है।

सॉफ्टवेयर से तय होगा नर्मदा परिक्रमा पथ

यात्रियों के लिए आश्रय स्थल बनेंगे, मंत्री पटेल बोले-तालाबों का काम पूरा कराएं अफसर



भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा पथ को सही तरीके से चिह्नित करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम ‘सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ है। इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नर्मदा परिक्रमा का मार्ग आसानी से तय किया जा सकेगा।

परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ‘रेडी टू स्ट्रे’ आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इन स्थलों की छत को सात लेयर से तैयार किया जाएगा, जिसमें बल्ले, बांस, मिट्टी, एमएस फ़ेम, प्रोफाइल शीट और मिट्टी के खम्पड़ जैसी प्राकृतिक चीजों का उपयोग होगा। दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेपन किया जाएगा, जिससे यह मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनेगा।

बैठक में परिक्रमा पथ और अन्य योजनाओं पर चर्चा- मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें नर्मदा परिक्रमा पथ के चिह्नंकन और यात्रियों के लिए आश्रय स्थल निर्माण पर चर्चा की गई। मंत्री ने सुझाव दिया कि करीब डेढ़ एकड़ में आश्रय स्थल बनाए जाएं, जहां यात्रियों के ठहरने और हरियाली की बेहतर व्यवस्था हो।

मंत्री पटेल ने चातुर्मास करने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने को कहा और सुझाव दिया कि इसमें समाजसेवी संगठनों और समितियों को मदद दी जाए।

जल संरक्षण के लिए खेत तालाबों का निर्माण होगा

मंत्री पटेल ने जल संरक्षण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले खेत तालाबों का निर्माण पूरा किया जाए ताकि पानी का सही तरीके से संरक्षण हो सके और भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर नर्मदा परिक्रमा के साथ-साथ जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में भी मददगार साबित होगा।

इंजीनियरिंग छात्र ने दसवीं की छात्रा से ज्यादाती की गर्भवती होने पर खुला राज, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पिपलानी इलाके में दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ ज्यादाती का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग छात्र ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद पीड़िता को मिलने बुलाया। तब उसने डरा धमकाकर किशोरी के साथ संबंध बनाए। इसके बाद बदनाम करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ ज्यादाती की। किशोरी के प्रेनेट होने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी दसवीं कक्षा की स्टूडेंट है। वह बागसेवनिया इलाके की एक बस्ती में रहती है। दो दिन अचानक ही किशोरी की तबीयत बिगड़ी, उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पता चला कि किशोरी गर्भवती है। अस्पताल से सूचना मिलते ही बागसेवनिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा किशोरी के बयान लिए गए। किशोरी ने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए अजय गुप्ता नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बात होने के साथ ही चैटिंग होने लगी। इसी दौरान जनवरी के महीने में अजय गुप्ता ने मुलाकात करने के बहाने किशोरी को बुलाया। इस दौरान वह किशोरी को अपने इंद्रपुरी स्थित किराए के कमरे पर ले गया। यहां पर उसने छात्रा की मर्जी के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद भी उसने कई बार किशोरी के साथ ज्यादाती की।

जयंती पर विशेष	
चेतनादित्य आलोक	
लेखक स्तंभकार हैं।	

निर्मल वर्मा का जन्म 03 अप्रैल 1929 को लोअर शिमला के कैथू स्थित हर्बर्ट विला नामक एक पुराने अंग्रेजी बंगले में हुआ था और उससे लगभग पचास मीटर की दूरी पर स्थित भज्जी हाउस में उन्होंने अपने जीवन के शुरूआती 15 वर्ष गुजारे थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने वाले निर्मल वर्मा पिछली सदी के 60 का पूरा दशक यूरोप में बिताने के बाद 1972 में दिल्ली लौटे थे। हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनकी पद्म भूषण, मूर्तिदेवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ जैसे कई पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया था। निर्मल वर्मा की चर्चित कृतियों में ‘रात का रिपोर्टर’, ‘एक चिथड़ा सुख’, ‘लाल टीन की छत’, ‘वे दिन’ आदि शामिल हैं।

बिम्बों के धुरंधर रचनाकार

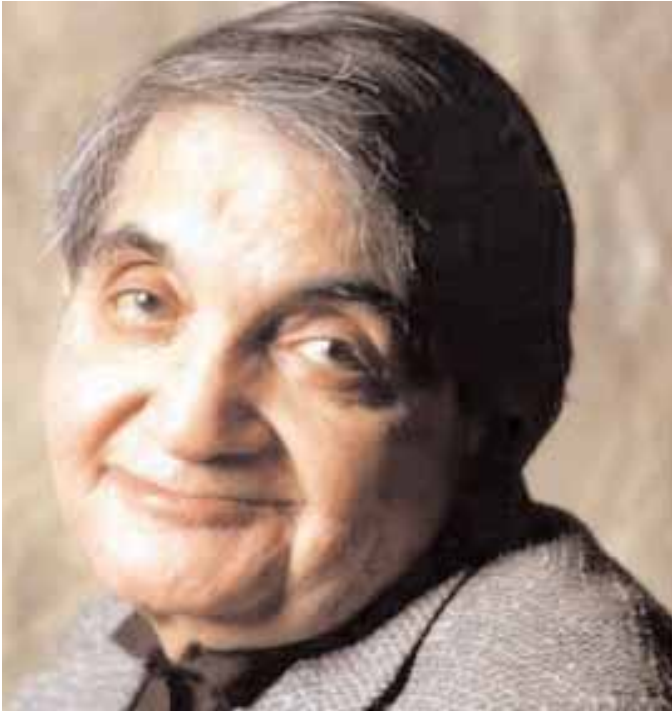
अनुभवों के धनी और बिम्बों के धुरंधर रचनाकार निर्मल वर्मा की कहानियों में परिवेश मुखरित होकर सामने आता है। लोअर शिमला के कैथू स्थित हर्बर्ट विला तथा भज्जी हाउस के आस-पास के इलाकों और परिवेश का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी साहित्य के इस निर्मल कथाकार को ‘लाल टीन की छत’ जैसा उपन्यास लिखने की प्रेरणा यहीं से मिली होगी। इसी प्रकार, दिल्ली और वहां के महानगरीय जीवन को समेटे निर्मल वर्मा के उपन्यास ‘एक चिथड़ा सुख’ में पिरोए गए अनगिनत बिम्बों के सहारे पाठक को न सिर्फ निर्मल वर्मा की नजर से दिल्ली को समझने में मदद मिलती है, बल्कि महानगरों के कठोर जीवन को भी करुणा पूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा इस उपन्यास से मिलती है। गौरतलब है कि ‘एक चिथड़ा सुख’ का नायक एक छोटे शहर से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने आता है, जहां पर उसे ‘मार्च की हल्की धुंध में सिर्फ एक गुम्बद दिखाई देता था- पेड़ों के ऊपर अटका हुआ। वह उन खंडहरों का हिस्सा था, जो मकानों की पीठ से पीठ लगाए दूर तक चले गए थे। पहले दिन जब यहां आया था तो उसे बहुत हैरानी हुई थी। दिल्ली भी कैसा शहर है! मुर्दा टीलों तले लोग जिंदा रहते हैं।’

अकेलेपन के कवि निर्मल वर्मा

दिल्ली और वहां के महानगरीय जीवन को समेटे निर्मल वर्मा के उपन्यास ‘एक चिथड़ा सुख’ में पिरोए गए अनगिनत बिम्बों के सहारे पाठक को न सिर्फ निर्मल वर्मा की नजर से दिल्ली को समझने में मदद मिलती है, बल्कि महानगरों के कठोर जीवन को भी करुणा पूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा इस उपन्यास से मिलती है। गौरतलब है कि ‘एक चिथड़ा सुख’ का नायक एक छोटे शहर से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने आता है, जहां पर उसे ‘मार्च की हल्की धुंध में सिर्फ एक गुम्बद दिखाई देता था- पेड़ों के ऊपर अटका हुआ। वह उन खंडहरों का हिस्सा था, जो मकानों की पीठ से पीठ लगाए दूर तक चले गए थे। पहले दिन जब यहां आया था तो उसे बहुत हैरानी हुई थी।

नई कहानी के प्रमुख कहानीकार

निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के ‘नई कहानी आंदोलन’ के प्रमुख कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनकी कहानियों में स्त्री-पुरुष संबंध, एकाकीपन, मानवीय अनुभूतियां, चिंता, तनाव, अवसाद और घनीभूत पीड़ा का चित्रण मिलता है। गौरतलब है कि शहरी मध्यमवर्गीय जीवन का संघर्ष, स्त्री-पुरुष संबंध, घर की तलाश एवं मानवीय अनुभूतियां उनकी अधिकतर कहानियों के केंद्र में स्थित हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों में मुख्यतः तीन विशेषताएं पाई जाती हैं- भाषाई काव्यात्मकता, रहस्यात्मकता एवं चमत्कारिक कल्पनाशीलता। यही तीन मुख्य विशेषताएं हैं, जो नई कहानी के दूसरे सभी कहानीकारों से, और शायद हिंदी की पूरी कथा-परंपरा से उनकी पृथक पहचान बनाती है। वैसे तो निर्मल वर्मा की सभी रचनाएं बहुत रोचक और पठनीय हैं, किंतु ‘परिदे’ शीर्षक उनकी कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय तथा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में से एक रही है। 1958 में प्रकाशित कहानी संग्रह ‘परिदे’ के संबंध में नामवर सिंह ने लिखा था- ‘फकत सात कहानियों का संग्रह परिदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम ‘नई कहानी’ कहना चाहते हैं, उसकी भी पहली कृति है।’ हालांकि, कई आलोचकों ने बाद में नामवर सिंह की इस स्थापना पर सवाल उठाए थे।



आत्मकथा लेखन के विरोधी थे

निर्मल वर्मा ने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, डायरी आदि जैसी अनेक विधाओं में भरपूर लेखन किया। इनके अलावा, यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने चैक साहित्य की रचनाओं का अनुवाद भी किया, पर उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। दरअसल, वे आत्मकथा लेखन के

विरोधी रचनाकार थे। एक बार उन्होंने स्वयं बताया था- ‘सिद्धांततः मुझे नहीं लगता कि एक लेखक को आत्मकथा लिखनी चाहिए। मुझे अपना जीवन सार्वजनिक करने में गहरा संकोच होता है।’ यही कारण है कि निर्मल वर्मा की संपूर्ण जीवनी आज भी अनुपलब्ध है। दुर्भाग्य से, विनीत गिल द्वारा लिखित पुस्तक ‘हियर एंड हियरआफ्टर: निर्मल वर्माज लाइफ इन लिटरेचर’ भी इस मामले में निराश ही करती है।

गैर हिंदी संसार में भी लोकप्रिय रहे

हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी निर्मल वर्मा के प्रशंसकों की एक अलग दुनिया है। देखा जाए तो हिंदी में निर्मल वर्मा के साहित्य के ऊपर पर्याप्त विवेचन-विमर्श तो उपलब्ध है ही, परंतु उन पर अंग्रेजी में भी लेखन कम नहीं हुआ है। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित निर्मल वर्मा अंग्रेजी की दुनिया में भी एक परिचित नाम हैं। उनके लेखन का विपुल मात्रा में अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है।

अंत तक पढ़ते रहे निर्मल

जीवन के आखिरी दिनों में गहन बीमारी से जूझते रहने के बावजूद निर्मल वर्मा लगातार पुस्तकें पढ़ते रहे। इस बारे में एक बार पत्नी गगन के पूछने पर उन्होंने कहा था- ‘सब प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही तो है, जिसके पास मानस (माईड) है, जिससे वह इस पृथ्वी पर अपने होने का अर्थ समझ सकता है। अंत

तक हमें इसका शोधन करना चाहिए।’ गौरतलब है कि वे एक साथ चार-पांच पुस्तकें पढ़ते थे। गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने समय व्यर्थ नहीं गंवाया। अंतिम समय तक हर दिन 12-13 घंटे काम करते रहे।

पत्र का जवाब अवश्य भेजते

निर्मल वर्मा दोपहर तक रचनाएं लिखते और भोजन के बाद पाठकों के पत्रों का जवाब देते थे। एक पोस्टकार्ड पर दो पंक्तियां ही सही, पर वे सभी पाठकों के पत्रों का जवाब अवश्य लिखते और शाम को स्वयं जाकर उन्हें डाकघर में डाल आते।

अकेलेपन के कवि

गौरतलब है कि बढ़ते औद्योगीकरण, तेजी से फैलते शहरों और कस्बों के बीच निर्मल वर्मा अपने सुजन में आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन का महाकाव्य रचते रहे। भीड़ में अकेले आदमी के जेहन को कागज पर पूरी संवेदना के साथ उतारने के लिए उन्हें ‘अकेलेपन का कवि’ भी कहा जाता है। ‘एक चिथड़ा सुख’ में दो पात्रों के बीच की खामोशी को व्यक्त करने के लिए निर्मल वर्मा ने अत्यंत सुदृढ़ भाव रचे हैं- ‘एक क्षण के लिए दोनों ठिठके रह जाते हैं। जैसे कोई चीज पीछे छूट गई हो। रूड़ियों के बासी, बोझिल धुंधलके में... कोई घाव... कोई खून की खरोंच...जिसकी पीड़ा बरसों बाद सर उठाती है। माफ़ी सी मांगती हुई, जबकि उसका कोई फायदा नहीं। बीती हुई स्मृति आने वाली पीड़ा को कभी माफ नहीं करती, यह उसने बरसों बाद जाना था।



भोजपुरी का संकट

डॉ. संतोष पटेल

खड़ी बोली भी बोली है हमारे भोजपुरी क्षेत्र में यह भाषा बन गई और भोजपुरी उसकी बोली कैसे? यह कैसे संभव हुआ जबकि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। माई की भाषा भोजपुरी है। करीब 20 करोड़ लोगों की भाषा है और सोलह देश में मौजूद है लेकिन हमालोगों की माई भाषा किसी अन्य भाषा को बताई जाती है। विद्यालयों में बाजासा पढ़ाई जाती है जबकि सत्य यह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, ना ही राष्ट्रीय भाषा है, हां, राजकाज की भाषा जरूर है जिसे हमने संविधान में 14 सितंबर 1949 में अंगीकार किया लेकिन इससे तो हमारी मातृभाषा कैसे बदल गई? यह सत्य है कि माई की बोली- बानी भी सत्ता बदल देती है और पूरी भाषा और संस्कृति पर दूसरी भाषा थोप दी जाती है जिसकी खुद की कोई संस्कृति नहीं है। अब इसका कारण क्या है जबकि आजादी के वक्त पढ़े लिखे हमारे लोग अधिक थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जो स्वयं भोजपुरी भाषी थे लेकिन मजाल कि किसी भी बड़े हमारे नेता ने हमारी भाषा को अस्मिता बोध से जोड़ा हो या शिक्षा का माध्यम बनाया हो। गजब का राष्ट्रवाद था। अब जब लोग इस सवाल करते हैं तो लोग बिहारियों को कहते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हिंदी पर हमला बोला है। इससे साफ है कि

हिंदी के साम्राज्यवाद ने भोजपुरी भाषियों को अपनी कॉलोनी बना रखा है।

‘Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature’ में न्गुगी वा थियेंगो भाषा, संस्कृति और औपनिवेशिक प्रभावों के बारे में गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि औपनिवेशिक शक्तियां ने अफ्रीकी लोगों के मन को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का उपयोग किया, जिसे वे ‘आध्यात्मिक अधीनता’ (spiritual subjugation) कहते हैं। उनकी प्रमुख बातों में से एक यह है कि अफ्रीकी लेखकों को अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति और पहचान को पुनर्जन्म दे सकें। चिनुआ अचेबे (Chinua Achebe), जो एक प्रसिद्ध नाइजीरियाई लेखक और विचारक थे, उन्होंने अपनी मातृभाषा और भाषा के महत्व के बारे में गहरे विचार व्यक्त किए। अचेबे मुख्य रूप से इग्बो (Igbo) समुदाय से थे, और उनकी मातृभाषा इग्बो थी। उन्होंने लिखा है कि ‘भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह एक समुदाय की आत्मा और उसकी विश्वदृष्टि को प्रतिबिंबित करती है।’ नोम चॉमस्की ने मातृभाषा के महत्व पर विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार, मातृभाषा हमारी पहचान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने परिवार, समाज और संस्कृति से जोड़ती है और हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है।



नोम चॉमस्की का LAD (लैंग्वेज एक्जिजिशन डिवाइस) सिद्धांत: नोम चॉमस्की ने अपने LAD सिद्धांत में कहा है कि मानव मस्तिष्क में एक विशेष प्रणाली होती है जो हमें

भाषा सीखने में मदद करती है। इस प्रणाली को चॉमस्की ने LAD या लैंग्वेज एक्जिजिशन डिवाइस कहा है।

चॉमस्की के अनुसार, LAD एक जन्मजात प्रणाली

सामयिक
आरबी त्रिपाठी
लेखक स्तंभकार हैं।

सेवाओं के निजीकरण के इस दौर में मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत का फैसला क्या आम लोगों, यात्रियों के लिये राहत भरा होगा? फिलहाल तो उम्मीद भर की जा सकती है। राज्य परिवहन निगम (एमपीएसआरटीसी) के बंद हो जाने के बाद से प्रदेश की यात्री परिवहन व्यवस्था लड़खड़ाते हुए मनमाने तरीके से तथा अंधी प्रतिस्पर्धा से चल रही लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य परिवहन निगम ने बरसों तक आम लोगों खासकर दूरस्थ स्थानों पर रहने वालों को ठीक-ठाक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई थी। लेकिन लगातार घाटे में चलती रापनि को एक ना एक दिन बंद तो होना ही था और वही हुआ भी। सरकार ने सफेद हाथी बन चुके इस निगम से तकरीबन 22 बरस पहले मुक्ति पा ली थी। इसके बंद होने के बावजूद भोपाल में पुराने आरटीओ ऑफिस के समीप इसके मुख्यालय का बॉर्ड टंगा रहकर इसकी याद दिलाता रहा। यह एक अलग मुद्दा है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में सार्वजनिक परिवहन निगम अच्छे से संचालित हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं तब रापनि को एकाएक क्या हो गया कि बंद करना पड़ा। आखिर कोई भी सरकार इस बोझ बन चुके निगम को कब तक ढोती। परिवहन विभाग के जिस बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को हाल ही में केबिनेट से मंजूरी मिली उसकी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुगम परिवहन सेवा के लिये बसों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय कंपनी बनेगी। इसके लिये राज्य सरकार 101.20 करोड़ की अंशपूजी देगी। इसका नियंत्रण राज्य स्तरीय कंपनी के पास रहेगा जिसमें 51 फीसदी शेयर सरकार और 49 फीसद शेयर निजी इन्वेस्टर के होंगे। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत सभागवार शहरों, गाँवों के लिये नये बस रूट बनाये जायेंगे। जरूरत के मुताबिक



किस रूट पर कितनी बसें चलेगी यह तय किया जायेगा। निजी ऑपरेटरों को परमिट मिलेगा, ई-टिकट की सुविधा मिलेगी जिससे कि यात्री ऑनलाईन टिकट बुक कर सकेंगे

जैसे कि रेलवे में होता है। मोबाइल एप से बसों के संचालन की लोकेशंस और अन्य जानकारी देखी जा सकेगी। बसों की निगरानी के लिये ऑनलाईन सिस्टम होगा तथा इलेक्ट्रिक

बसों के संचालन को बढ़ावा दिया जायेगा। रापनि के समय तो मोबाइल फोन ही नहीं थे तो सब कुछ मैनुअल तरीके से चलता था।

ऊपर वर्णित बातें हालांकि जानने पढ़ने में भले ही अच्छी लगें, जरूरत इस बात की है कि ये सही रूप से धरातल पर आ जायें और आम यात्री को इनका लाभ मिल सके। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदेश में पहले से चल रही निजी बसों के रूट और निर्धारित टाइम का क्या होगा। अभी पुणे, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों के लिये चल रही लक्जरी एसी बसों का संचालन यथावत रहेगा या इनमें कोई तब्दीली होगी। इन बसों में कथित तौर पर मनमाने ढंग से वसुले जाने वाले किराये और त्याहारों तथा विशेष अवसरों पर किराये में अधोषित वृद्धि को कैसे रोका जायेगा। हो सकता है इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जायें या ना भी मिलें। लेकिन कुछमिलाकर यात्रा को सुगम के साथ सुरक्षित तथा सस्ती करने पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिये ताकि आम लोगों यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सके।

राज्य परिवहन निगम की बसों में अपन ने भी बहुत सारी यात्राएं की है जिसके अच्छे बुरे कभी ना भुलाये जाने वाले अनुभव रहे हैं। उस समय बस कंडक्टर की नौकरी के लिये और फिर ठीक-ठाक रूट मिल जाये इस हेतु बड़ी होड़ मचती थी। कंडक्टर के ऊपर टिकट चेकर और उड़नदस्ता हुआ

करता था जो आकस्मिक रूप से कभी भी कहीं भी बीच रास्ते प्रकट होकर बेटिकट यात्रियों की जांच पड़ताल करता था। हालांकि यह भी सही है कि कंडक्टर से लेकर चेकर, डिपो से मुख्यालय तक कथित तौर पर एक अधोषित चैन सिस्टम चला करता था। इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सका।

रापनि के डिपो हुआ करते थे जहां गाड़ियों की मरम्मत और सुधार के साथ और भी बहुत कुछ होता था। इनमें मैकेनिकों के साथ डिपो मैनेजर रहते थे। गल्ली से भी बीच रास्ते बस में तकनीकी खराबी आने या टायर पंचर अथवा ब्रस्ट हो जाने पर यात्रियों की जैसे शामत आ जाती थी। या तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था या किसी दूसरी बस के गुजरने पर उस बस में ‘एलाउ’ किये जाने की स्थिति में खड़े रहकर यात्रा करनी पड़ती थी।

इन पुरानी रापनि सेवाओं का उल्लेख करना इसलिये भी प्रासंगिक है कि नई व्यवस्था में इन्हें ध्यान में रखकर फैसले लिये जायें। हमने रापनि की लंबी दड़ताल के समय चलाई गई निजी बस ऑपरेटरों की कथित मनमानी, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा आपातकाल के समय सारी व्यवस्थाएं समय पर संचालित होने का दौर भी देखा है। सो, सार्वजनिक परिवहन को सुगम, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनाना आवश्यक है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर सेवा मिल सके।

चार साल की मासूम को ट्रक ने कुचला

»सड़क किनारे पिता के साथ बाइक पर बैठी थी, आरोपी चालक फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल-बैरसिया रोड पर रतुआ में मंगलवार की रात एक ट्रक ने सड़क किनारे बाइक पर बैठे पिता और मासूम बच्ची को चपेट में ले लिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। जबकि पिता की हालत नाजुक बनी है। परिवार सीहोर में रहने वाले रिश्तेदार के घर से ईद मनाकर बैरसिया के लिए लौट रहा था। घटना के समय परिवार चाय-पानी पीने के लिए ढाबे पर रुका था।

ईद मनाने सीहोर गया था परिवार

आमना अली (4) पुत्री सैयद जाहिद अली बैरसिया के शेरपुरा की रहने वाली थी। इसी साल परिजनों ने उसे नर्सरी क्लास में एडमिट कराया था। मृतका के चाचा जोएब ने बताया कि उसके पिता बैरसिया में गारमेंट शॉप का संचालन करते हैं। ईद के मौके पर जाहिद पत्नी और बेटी को लेकर सीहोर में रहने वाली बहन के घर ले गए थे।

चाय पीने के लिए रुका था परिवार

गुनगा थाना इलाका स्थित रतुआ में परिवार एक ढाबे पर चाय और पानी पीने के लिए रुक गया। हाईवे पर बने ढाबे पर पिता और बेटी बाइक पर बैठे रहे। जबकि बच्ची की मां बाइक से उतरकर पानी पी रही थीं। तभी बैरसिया तरफ से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे बाइक पर बैठे पिता-पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। जबकि बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। बुधवार की सुबह हमीदिया अस्पताल की मॉर्चुरी में शव का पोएम कराया जा रहा है।

गोद से गिरी चार महीने की मासूम, बस ने कुचला

भोपाल (नप्र)। भोपाल स्टेशन के करीब 100 मीटर दूर हबीबिया तिराहा पर बुधवार दोपहर कॉलेज बस से टकरा लगने के बाद मां की गोद से चार माह की मासूम गिर गई। बस के पिछले टायर के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मां के हाथ में चोट आई है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पति से विवाद के बाद बच्ची को लेकर आज सुबह ही मंडीदीप से भोपाल आई थी। मामले में पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है। घटना की हर एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

मंडीदीप की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं पिता: टीआई जीतेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि दखत सिंह सतलापुर मंडीदीप में रहते हैं और वहीं एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी गीता है और 4 महीने की बेटी दीक्षा है। बुधवार की सुबह किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पत्नी बच्ची को लेकर बिन बताए घर से निकल गई। ट्रेन से भोपाल स्टेशन आई, यहां कुछ देर आस पास घूमने के बाद वह हबीबिया तिराहा पर पहुंची।

बस से टकराते ही हाथ से छूटी बच्ची

यहां सामने से आ रही कॉलेज बस को देखकर मां घबरा गई। उसने पीछे होने का प्रयास किया, इस बीच मां का हाथ बस से टकरा गया। गोद में मौजूद बच्ची उछलकर गिर गई। इससे बच्ची का सिर बुरी तरह से जखमी हो गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मंत्री नागर चौहान ने बनासकांठा पहुंच कर घायल श्रमिकों का हाल जाना



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने अधिकारी-कर्मचारियों के साथ देर रात गुजरात के बनासकांठा पहुंचकर मध्यप्रदेश के घायल श्रमिकों एवं उनके परिजन से मुलाकात कर हाल-चाल जाना। मंत्री श्री चौहान ने घायल श्रमिकों के परिजन से बात कर उन्हें ढाढस बंधाया। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा घायल मजदूरों के उचित इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुजरात, बनासकांठा में घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त की। बनासकांठा जिले के डीसा अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों के इलाज के लिये उचित प्रबंध के निर्देश दिए। साथ ही घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्थानीय प्रशासन दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी करेगा। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हादसे में मृतक एवं घायल श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल मृतकों के परिजनों को रुपये 2-2 लाख तथा घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये और गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये एवं घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

जनपद

भाजपा की आगामी कार्य योजना को लेकर जिला बैठक हुई

6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस से 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे

धारा। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की आगामी कार्य योजना को लेकर जिला संगठनात्मक बैठक 2 अप्रैल को भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा संगठन जिला प्रभारी श्याम बंसल भाजपा जिला अध्यक्ष निलेश भारती विधायक नीना वर्मा पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने संबोधित किया। सर्व प्रथम अतिथियों द्वारा भारतमाता व पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण व दीपप्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री दिलीप पटोदिया खेमराज पाटीदार महेन्द्र सिंह चाचू बना वेलसिंह भुरिया जिला महामंत्री प्रकाश धाकड़ मंचासीन रहे। स्वागत उद्बोधन भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ने दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने श कहा कि इस बार 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस पर ऐसा संयोग बना की उस दिन



भगवान राम जी का प्राकट्य उत्सव राम नवमी है इसलिए उत्साह भी दुगुना होना चाहिए। संगठन जिला प्रभारी श्याम बंसल ने कहा कि 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस से 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अंबेडकर जी जयंती तक अनेक कार्यक्रमों आयोजित होंगे जिसमे 3 और 4 अप्रैल को मंडल स्तर पर भाजपा की बैठक आयोजित करना 6 एवं 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा एकत्रित

होकर हर्षोल्लाह के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाना है। हर घर भाजपा का ध्वज लगाना। इसी प्रकार 7 से 13 अप्रैल के बीच एक बूथ स्तर सम्मेलन होगा जिसका नाम बस्ती गांव चलो अभियान होगा और इसमें पार्टी के नगर और प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी एक-एक बूथ पर जाएं और कम से कम 8 घंटे वह कार्यकर्ता उस गांव मोहल्ले एवं बस्ती में वहां के रहवासियों के साथ व्यतीत करेंगे एवं पार्टी द्वारा दिया

सतपुड़ा में बाबू को सरपेंड किए जाने पर नारेबाजी, प्रदर्शन

आदिम जाति कल्याण विभाग में कमिश्नर की कार्रवाई का विरोध, हंगामे के बाद समझौता बैठक



भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग के कमिश्नर से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को दफ्तर में जमकर हंगामा कर दिया। कर्मचारियों की नाराजगी एक बाबू को सरपेंड किए जाने को लेकर थी। नाराज कर्मचारियों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच आखिरकार अफसरों को समझौता बैठक बुलानी पड़ी। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी बंद कमरे में चर्चा करने को लेकर तैयार नहीं हुए।

मंत्रालय के समीप सतपुड़ा भवन में यह हंगामा आज सुबह दफ्तर खुलने के साथ शुरू हुआ।

इसके बाद एकजुट हुए कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए एकजुट हो गए। जमकर हंगामे और नारेबाजी के बीच कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए दोपहर 12 बजे अधिकारी इस मामले में समझौता बैठक के लिए तैयार हुए। लेकिन कर्मचारी संगठन और कर्मचारी बंद कमरे में बैठक करने के बजाय खुले में चर्चा करने के लिए दबाव बनाते रहे।विभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला के द्वारा एलडीसी के सरपेंड किए जाने पर विरोध शुरू हो गया। इसलिए हुआ विवाद-घटना को लेकर कर्मचारियों का

कहना है कि आज सुबह आदिम जाति कल्याण विभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला ने एलडीसी हर्षपाल को फोन किया और कहा कि जल्दी आफिस आ जाओ, आदेश टाइप करना है। बाबू हर्षपाल ने कहा कि आता हूं। इसके बाद वह दस बजे पहुंचा तो कमिश्नर शुक्ला ने उसे डांटते हुए सरपेंड करने की जानकारी दी और भला बुरा कहा। बोतल उस पर फेंककर मारी। इसके बाद कर्मचारियों को जानकारी लगने पर सभी एकजुट हो गए और हंगामा कर नारेबाजी करने लगे। विवाद बढ़ता देख कमिश्नर शुक्ला ने पुलिस बुला ली लेकिन तब भी हंगामा नहीं थमा। इसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बैठक कर समझौता करने का निर्णय हुआ लेकिन समझौता हो नहीं सका है।

आज दिन भर काम नहीं करेंगे, सरपेंशन खत्म नहीं हुआ तो आंदोलन: कर्मचारियों के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला के विरुद्ध नारेबाजी के बाद कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने दफ्तर के गेट में बैठकर सीटिंग की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने दफ्तर के कर्मचारियों को समझाया कि कोई कर्मचारी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा लेकिन काम भी नहीं करेगा। अगर कोई अधिकारी कोई फाइल मांगे या कुछ काम करने को कहेगा तो भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि कमिश्नर के एक्शन के बाद भी किसी अधिकारी ने साथ नहीं दिया है। सभी कर्मचारी ऐसी स्थिति में अधिकारी को मना करेंगे। अगर शाम तक कमिश्नर कर्मचारी का सरपेंशन वापस नहीं लेते हैं तो ज्ञापन के माध्यम से आंदोलन की जानकारी दी जाएगी और फिर कर्मचारी प्रदर्शन आंदोलन तेज करेंगे।

एम्स भोपाल के डॉ. अविनाश ठाकरे का यूपी एसएसओपीआईसीओएन 2025 में अतिथि व्याख्यान

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के कुशल नेतृत्व में, संस्थान वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

एम्स भोपाल ने मरीजों और आगंतुकों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की

भोपाल। गर्मी के आगमन के साथ, एम्स भोपाल ने अपने मरीजों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए अपने परिसर में कई स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा स्थापित की है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और ठंडे पेयजल तक आसान पहुंच प्रदान करना है, जिससे भीषण गर्मी के महीनों में जलयोजन और आराम बना रहे। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा, एम्स भोपाल में, मरीजों की देखभाल और जनकल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच स्वास्थ्य बनाए रखने और

निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक हो जाती है। ये नई जल सुविधाएं यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं कि हमारे मरीज, उनके परिवारजन और सभी आगंतुक आरामदायक और हाइड्रेटेड रहें। हम सतत रूप से मरीजों के अनुरूप सेवाओं और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पहल एम्स भोपाल की मरीजों की भलाई और जनस्वास्थ्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगंतुकों और मरीजों को संस्थान में एक आरामदायक और सहयोगी वातावरण प्राप्त हो।

साफ-सफाई एवं परिसरों को सजाने के साथ ही शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा और 14 अप्रैल को डॉ अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ ही मिष्ठान वितरण भी किया जाएगा उसके पश्चात संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि धार जिला संगठन की बैठक में धार विधानसभा, बदनावर और सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के अपेक्षित भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। जिसमें भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मोर्चा जिला अध्यक्ष / महामंत्री मंडल अध्यक्ष / मंडल प्रभारी आजीवन सहयोग निधि जिला प्रभारी, सह प्रभारी जिला पंचायत अध्यक्ष /उपाध्यक्ष जनपद अध्यक्ष /उपाध्यक्ष नगर पालिका /नगर परिषद अध्यक्ष प्रकोष्ठ जिला संयोजक सहित विशेष रूप से आमंत्रित भाजपा नेता उपस्थित रहे।

विद्यार्थी एक अच्छे इंसान जरूर बने : कलेक्टर

भविष्य से भेंट कार्यक्रम में सीएम राइज विद्यालय धार में कलेक्टर ने सुनाए संस्मरण, विद्यार्थियों के प्रश्नों के दिए उत्तर,बांटे उपहार



धारा। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत बुधवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्र जिला मुख्यालय स्थित सीएम राइज विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें अनेकों प्रेरणादायक संस्करण सुनाएं । विद्यार्थी कलेक्टर मिश्र को अपने बीच पाकर अत्यंत उत्साहित थे।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों के अनेकों प्रश्नों के उत्तर भी दिए और उपहार स्वरूप उन्हें ने कॉपी एवं पेन दिए। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ में एक अच्छे इंसान जरूर बने तथा शिक्षकों की डांट का कभी बुरा ना माने,शिक्षक उनकी भलाई के लिए ही उन्हें डांटते हैं, यह बात बहुत समय बाद उन्हें समझ आती है। इससे पूर्व कलेक्टर मिश्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। सीएम राइज विद्यालय के प्राचार्य डॉ स्मृति रत्न मिश्र ने कलेक्टर ने स्वागत किया और विद्यालयीन गतिविधियों की जानकारी दी।

सौ प्रतिशत परीक्षा परिणाम की बात जानकर कलेक्टर ने विद्यालयीन स्टाफ को शुभकामनाएं दी कलेक्टर ने ली सेल्फी-सीएम राइज विद्यालय पहुंचने पर छात्राओं ने तिलक

लगाकर प्रियंक मिश्र का स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्कूल चले हम थीम पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली विद्यार्थियों के प्रश्नों के दिए उत्तर - भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर से विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे जिनमें माधुरी ठाकुर, कृष्णा मेहरा,लव वैष्णव, सोनाक्षी अभिषेक सुहानी दुबे आदि थे। प्रमुख प्रश्नों में आप कलेक्टर कैसे बने,आप कलेक्टर ही क्यों बने? कलेक्टर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या हिंदी माध्यम से भी कलेक्टर बन जा सकता है?

कलेक्टर के पास बहुत काम रहते हैं आप कैसे मैनेज करते हैं? आदि थे । कलेक्टर ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब बहुत ही रोचक अंदाज में दिया। छात्रा ने कलेक्टर को भेंट की पेंटिंग- सीएम राइज विद्यालय की कक्षा आठवीं की छात्रा एंजेल डोडिया ने कलेक्टर प्रियंक मिश्र को पेंटिंग भेंट की। अपना चित्र देखकर कलेक्टर प्रसन्न हुए । कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर द्वारा विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए जाने के साथ साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन सोनी शर्मा ने किया।

ताप विद्युत गृहों ने किया रिकॉर्ड 28789.8 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन

मेगावाट है।

किस विद्युत गृह का कैसा रहा प्रदर्शन

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के 210 मेगावाट स्थापित क्षमता के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई ने 1546 मिलियन यूनिट, 500 मेगावाट स्थापित क्षमता के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी ने 3756 मिलियन यूनिट, 1340 मेगावाट स्थापित क्षमता के संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर ने 8445 मिलियन यूनिट व 2520 मेगावाट स्थापित क्षमता के श्री सिंगाजी ताप

विद्युत गृह दोंगलिया ने 15042 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया।

संजय गांधी ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर 3 ने किया कमाल

संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 3 ने 4116 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर रिकार्ड बनाया। यह इस यूनिट के इतिहास में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है।

तवफ बोर्ड

कौसर जहां

(लेखिका दिल्ली स्टेट हज कमटी की अध्यक्ष हैं।)

तवफ बोर्ड अधिनियम में संशोधन कानून समय के अनुरूप जरूरी लदान है। आम मुसलमानों को इस मुद्दे पर भडकाने का प्रयास कर रहे कट्टरपंथी तत्व अपनी कौम और देश का बडा नुकसान कर रहे हैं। वास्त्व में अगर कोई भी समाज सही दिशा में हो रहे परिवर्तन को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर स्वीकार नहीं करता तो वह जडता का शिकार हो जाता है।

समय के अनुरूप शिकार के साथ परिवर्तन ही प्रगति का सही रास्ता है। यह मुस्लिम समुदाय में अधिकांश लोगों को समझ आ गया है लेकिन उनको भडकाने की एक सुनियोजित साजिश हो रही है। मैं तर्क सहित कई मुस्लिम विद्वानों से बात करके जानने की कोशिश कर चुकी हूं कि वक्फ सुधार से आखिर आम मुसलमान को फायदा है या नुकसान? कोई भी मुझे यह नहीं समझा सका कि देश के आम मुसलमान का एक भी नुकसान होगा। हां, आम मुसलमान के नाम पर ठेकेदारी करने वालों को इस बात का डर जरूर है कि कहीं उनकी दुकान न बंद हो जाये। उनके अवैध कब्जों की पोल न खुल जाये। जिस संपत्ति का उपयोग आम मुसलमान की बेहतरी के लिए होना चाहिए था उसके दुरुपयोग का भोंडा न फूट जाये। अपने इस धर के लिए कट्टरपंथी आम मुसलमान को ढाल बनाना चाहते हैं।

मेरा स्पष्ट मानना है कि आम मुसलमान को वक्फ सुधारों से फायदा है। यह चंद लोगों के एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास है जिसका स्वागत होना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में इस पर व्यापक चर्चा हुई तो वहां भी विपक्ष और कौम का नुकसान करने का ठेका ले चुके नेताओं ने विध्वंसक

आज पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट, निगमायुक्त के खिलाफ आ सकता है निंदा प्रस्ताव

»संपत्तिकर और जलकर वृद्धि पर विरोध हो सकता है

»भाजपा और कांग्रेस ने बैठक में रणनीति बनाई

भोपाल (नप्र).। भोपाल नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट गुरुवार को पेश होगा। नगर निगम की परिषद का साधारण सम्मेलन सुबह 11 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) स्थित परिषद सभागृह में आहूत किया गया है।

निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आहूत सम्मेलन में कार्यसूची में सम्मिलित विषयों पर चर्चा की जाएगी। महापौर मालती राय द्वारा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट और वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट बैठक से पहले बुधवार शाम को भाजपा और कांग्रेस पार्षद दल बैठक

हुई। दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने बजट बैठक को लेकर रणनीति फाइनल की। बैठक में जहां निगमायुक्त हरेंद्र नारायण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है।

कांग्रेस टैक्स वृद्धि का करेगी विरोध-कांग्रेस पार्षद टैक्स वृद्धि को लेकर महापौर को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार संपत्तिकर में 10 प्रतिशत और जलकर व बड़ेतरी बजट बैठक में हंगामा का कारण बनेगी। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष टैक्स में वृद्धि को रोक पाती है या नहीं। भाजपा और कांग्रेस पार्षद मिलकर निगमायुक्त के अड़ियल रवैया को लेकर खासे नाराज है। लिहाजा उनके खिलाफ भाजपा और कांग्रेस पार्षद निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे।

बाग प्रिंट

ताहिर अली

(लेखक सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसमर्पक हैं)

मध्यप्रदेश के धार जिले का छोटा सा कस्बा ‘बाग’ केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक समृद्ध हस्तकला का केंद्र है। यहां विकसित हुई ‘बाग प्रिंट’ की कला सदियों पुरानी विरासत को जीवित रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। यह हस्तशिल्प कला प्राकृतिक रंगों और हाथ से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉकों के माध्यम से कपड़ों पर एक अनोखी छाप छोड़ती है। इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मोहम्मद यूसुफ खत्री और उनका परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके अथक प्रयासों ने बाग प्रिंट को भारत और वैश्विक मंच में एक विशिष्ट पहचान दिलाते है।

बाग प्रिंट: ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जागरण—बाग प्रिंट की परंपरा सदियों पुरानी है और यह मूल रूप से खत्री समुदाय द्वारा संरक्षित और संवर्धित की गई। पहले यह कला केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीकों और मिलावट भरें रंगों के चलते इसकी पारंपरिक पहचान खतरे में पड़ने लगी। बाग प्रिंट को विलुप्त होने से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वर्गीय इस्माईल खत्री की रही। उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए परंपरागत तकनीकों में नवाचार किए और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को सतस्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।बाग प्रिंट की इस समृद्ध परंपरा को जीवित रखने में मो. यूसुफ खत्री, स्व. मो. अब्दुल कादर खत्री, श्रीमती रानीबी बी खत्री, बिलााल खत्री, मो. रफीक खत्री, उमर मो. फारूख खत्री, मो. काजीम खत्री, मो. आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मो. खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री और मोहम्मद अली खत्री जैसे शिल्पकारों का उल्लेखनीय योगदान है।यह परिवार कला, नवाचार और परंपरा के संतुलन को बनाए रखते हुए, बाग प्रिंट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बाग प्रिंट को जीवंत रखने और वैश्विक पहचान दिलाने में खत्री परिवार दशकों से दे रहा है योगदान—बाग प्रिंट को आज के दौर में जीवित रखने और आगे बढ़ाने में खत्री परिवार की कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। उनके परिश्रम और समर्पण ने इस कला को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। एक

एजेंडा अपनाया। इन्होंने सार्थक सुझाव के बजाय चर्चा को रोकने का प्रयास किया। फिर भी जेपीसी रिपोर्ट के बाद मेरा दृढ़ मत है कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उन्हें भी यह समझ आएगा कि यह उनकी भूल थी। यह सुधार मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए हैं। यह पारदर्शिता के लिए सुधार हैं और भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त होने का रास्ता इन सुधारों में है।

आज मुस्लिम समाज के बीच इस बात की छटपटाहट है कि वे कैसे स्वयं को कट्टरपंथी ताकतों के दबाव से मुक्त करके सुधारों का हिस्सा बनें। मुस्लिम समाज जडता से निकल कर कौम की बेहतरी का रास्ता चाहता है। वह विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है।

मुस्लिम महिलाएं भी चाहती हैं कि उनकी समान भागीदारी का रास्ता खुले। कोई भी समाज अपनी महिलाओं को पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वे कट्टरपंथी भला इसका समर्थन कैसे करेंगे जो हमारी बहनों को तीन तलाक की बेड़ी से भी मुक्त नहीं होने देना चाहते थे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीन तलाक प्रथा खत्म करने का कानून बना तो सबसे ज्यादा खुश मुस्लिम महिलाएं ही थीं। वक्फ में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव से भी वैसी ही स्वाभाविक खुशी है। महिलाएं संवेदनशील होती हैं। उनकी भागीदारी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ेंगी तो इस संस्था में नये विचार भी आयेंगे।

वास्त्व में वक्फ सुधार का कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन देर आयद दुरुस्त आये। अब मोदी सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधार कर नई व्यवस्था के लिए जो संशोधन प्रस्तावित किए

परिवहन के भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही मप्र सरकार : सुश्री संगीता शर्मा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का ट्वीट, भूपेंद्र और गोविंद की अवैध सम्पत्ति की जांच कराए सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सीधा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने एक ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की निष्क्रियता कोई लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश है, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। सुश्री शर्मा ने ट्वीट में लिखा, यह मध्यप्रदेश सरकार की तोता (जांच एजेंसी) लोकायुक्त की लापरवाही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के संगठित और सुनियोजित भ्रष्टाचार में सालों से सलिस भाजपा नेताओं, भाजपा के मप्र प्रभारियों, संगठन के अन्य पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत (अब खाद्य मंत्री) को बचाने की मोहन यादव सरकार की कारगुजारी है। सुश्री शर्मा ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा कि, अगर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, क्या आपने लोकायुक्त की इस निष्क्रयता की समीक्षा की? आखिर आप किसे बचाना चाह रहे हैं-भूपेंद्र सिंह, जिनके कार्यकाल में इस भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, या गोविंद सिंह राजपूत, जिनके कार्यकाल में

हैं उससे वक्फ बोर्ड ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर पाएगा। यह सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप है। जिसकी वकालत कभी यूपीए के लोग करते थे। वोट की राजनीति ने विपक्ष की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है।

लेकिन मोदी सरकार ने वोट के लिए नहीं, देश के लिए फैसले करने का साहस दिखाया है। वक्फ संशोधन वक्त की जरूरत है और संविधान की भावना के अनुरूप है। संविधान की बुनियाद ही बराबरी के सिद्धांत पर टिकी है। फिर महिलाओं से भेदभाव का अधिकार भला संविधान कैसे दे सकता है। जो लोग इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह इबादत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन का मामला है। संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आज वक्फ को चुनिंदा लोगों के चंगुल से मुक्त करना जरूरी है।

अधिनियम में संशोधन करके एक पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के उपेक्षित तबकों की भागीदारी का इंतजाम संशोधन में किया गया है। वहीं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर मोदी जी की सरकार ने अपनी इस सोच को पुष्टा रूप से सामने रखा है कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है तो महिलाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्हें हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देना होगा।

वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो, उनका सही मूल्यांकन किया जाये। भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करके संपत्ति के अनुपात में राजस्व की व्यवस्था हो, आखिर इसमें क्या बुराई है? कोई भी बोर्ड या निकाय तभी प्रभावी होता है जब उसके संचालन और

यह लूट खुलकर हुई, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कहने पर गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग सौंपा गया? **जिरो टॉलरेंस पर खामोशी क्यों:** कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भ्रष्टाचार पर जिरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व मंत्रियों की अवैध संपत्तियों की जांच करवाने के बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को कमजोर कर रही है। उन्होंने ट्वीट में यह भी पूछ कि, क्या सरकार ने लोकायुक्त को परिवहन विभाग के करोड़पति सिपाही सौरभ शर्मा के खिलाफ चालान पेश करने से रोका है?

सख्त कार्रवाई की मांग : कांग्रेस ने मांग की है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में सौरभ शर्मा के साथ-साथ पूर्व परिवहन मंत्रियों भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की अधोषित संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी मंत्री इस तरह की लूट न कर सके। सुश्री शर्मा ने कहा है कि 4 साल बाद भाजपा को जनता के सामने भी जाना पड़ेगा तब इस संगठित भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की थी इसका हिसाब तो देना पड़ेगा।

प्रबंधन में पारदर्शिता हो और जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। यही प्रयास नये संशोधनों के माध्यम से सरकार ने किया है। कोई भी व्यवस्था बिना जवाबदेही के निरंकुश हो जाती है। नये प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि वक्फ संपत्ति को निष्पक्ष तरीके से चिह्नित किया जाये और अगर कोई विवाद है तो उसका समुचित कानूनी निस्तारण हो। कानून इस लोकतंत्र में सर्वोपरि है।

मेरा मानना है इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड ज्यादा सक्षम होगा। ज्यादा पारदर्शिता से काम करेगा और ज्यादा जवाबदेह होगा। आखिर कौन से लोग हैं जो वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने का विरोध करना चाहते हैं। नियमन से ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी।

कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी। इसका विरोध क्या महिलाओं का विरोध नहीं है। सेक्शन-9 और 14 में बदलाव करके केन्द्रीय वक्फ परिषद में दो महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगाखानी मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान होना क्यों गलत है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक अमुक समूह का ही वक्फ पर कब्जा होगा। मेरा मानना है कि पुराना कानून मुसलमानों को बाँटने वाला कानून था। हमें एलीट सोच पर आधारित पुराने कानून की जगह सर्वसमावेशी नए कानून का स्वागत करना होगा।

वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर-मुस्लिम एकसपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ का ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का

एम्स भोपाल में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन सफाई और स्वास्थ्य की ओर एक कदम

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के संघर्ष को साकार करना है। स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य अस्पताल एवं उसके परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर प्रो. सिंह ने स्वच्छता शपथ ग्रहण करवाई, जिसमें उन्होंने सभी संकाय, कर्मचारियों और छात्रों से एक स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक-मुक्त परिसर बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करने और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा मिल सके। इस अभियान के तहत प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने स्वयं

पेंशनरों ने केंद्र के समान देय तिथि से डीआर मांगा

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई राहत भुगतान करने की मांग की है एसोिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित्त को लिखे पत्र में जुलाई 2024 से 3३ एवं जनवरी 2025 से 2 त्र प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। सक्सेना ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय मानक नीति के विरुद्ध राज्य शासन लगातार अवधि में कटौती कर रही है, जो सवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। एसोसिएशन के

हिसाब–किताब पारदर्शी बनेगा। इसका कोई भी आम मुसलमान भला क्यों विरोध करे? मुस्लिम मौलवी या जो भी तत्व विरोध कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि मुसलमानों की शिक्षा और उनकी बुनियादी जरूरतों को बेहतर करने के लिए उन्होंने कब कोई आंदोलन किया। केंद्र सरकार अब कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। इसका विरोध वही करेगा जिसके मन में भ्रष्टाचार से बचने का खौफ हो।

कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। आखिर यह सिफारिशें गैर मुसलमानों की तो नहीं थीं। यह पढे लिखे मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे थे जो कट्टरपंथियों की नहीं कौम की बेहतरी चाहते थे। वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कम्प्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से पारदर्शिता आएगी। न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आखिर विवाद से समाधान की ओर बढने का रास्ता किसे पसंद नहीं आ रहा। यह तो अच्छी पहल है।

मेरा मानना है कि मुसलमानों को गुमराह करने वाले लोग कभी भी कौम के रहनुमा नहीं हो सकते। आज वक्फ सुधारों का विरोध करने वाले लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि वे अपनी ही कौन की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए खडे हो रहे हैं। लेकिन दबाव के आगे कभी भी कोई सार्थक बदलाव दम नहीं तोड़ सकता। मेरा दृढ़ मत है कि मोदी सरकार इन भड़काने वाले तत्वों के सामने नहीं झुकेगी। देश का आम मुसलमान इन परिवर्तनों का इंतजार कर रहा है।

श्रमदान एवं वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा, स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आदत है, जो हम सभी के लिए एक स्वस्थ और सतत पर्यावरण सुनिश्चित करती है। स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से हम जागरूकता फैलाने और स्वच्छता एवं स्वस्थता के प्रति समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मचारियों के लिए टीकाकरण का समावेश उन निस्वार्थ योद्धाओं को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एम्स भोपाल को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में अहर्निश योगदान देते हैं। इस पहल में उपनिदेशक (प्रशासन) कर्नल (डॉ.) अजीत कुमार, डीन (एकेडमिक्स) (डॉ.) रजनीश जोशी, कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक प्रो. (डॉ.) शशांक पुरवार, सहायक चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अंजन साहू तथा डॉ. बबिता रघुवंशी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा की मुद्रास्फीति के कारण पेंशन के वास्तविक मूल्य में आई गिरावट की पूर्ति महंगाई राहत देकर की जाती है किंतु सरकार के द्वारा देय तिथि से डी आर का भुगतान नहीं करने के कारण प्रदेश के पेंशनर तंग हाल में जीवन यापन कर रहे हैं। जो अत्यधिक कष्टदाई है । भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि शासन को वृद्ध पेंशनरों को महंगाई राहत देने के भेदभाव रहित आदेश शीघ्र जारी करना चाहिए एवं मांग की है कि पूर्व के महंगाई राहत अवधि में कटौती कर रही है, जो सवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। एसोसिएशन के

लोक कला और मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला को मिलाकर बाग प्रिंट को विशिष्ट पहचान दी। उनके प्रयासों से कई महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण मिला, जिससे यह कला रोजगार का माध्यम बनी।

स्व. अब्दुल कादिर खत्री – स्वर्गीय अब्दुल कादिर खत्री, इस्माईल खत्री के पुत्र, बाग प्रिंट के एक अनुभवी शिल्पकार थे, जिन्होंने इस हस्तकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने पारंपरिक डिजाइनों में आधुनिकता जोड़ते हुए इसे नया रूप दिया और इसे व्यावसायिक रूप से स्थापित करने में मदद की। वे निपट (नई दिल्ली, अहमदाबाद) जैसे प्रमुख फैशन संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षण देते थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को और वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। रशीदा बी खत्री (पती स्व. अब्दुल कादिर खत्री) – रशीदा खत्री ने अपने ससुर इस्माईल खत्री और पति अब्दुल कादिर से बाग प्रिंट की कला सीखी और उनके निधन के बाद भी इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने बैम्बू, लैटर और जूट पर बाग प्रिंट के प्रयोग किए, जिससे इस कला का विस्तार हुआ। उन्हें राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में बाग प्रिंट कला को सराहा—प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एम्पी पवेलियन का अवलोकन किया। जहां मध्यप्रदेश के हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और स्थानीय उद्योगों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाग प्रिंट के युवा शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री के स्टॉल का अवलोकन किया और खुद बाग प्रिंट का ठप्पा लगाकर इस पारंपरिक कला की महत्ता को रेखांकित किया। इस अवसर पर राज्यापाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 13 राजदूत, 6 उच्चायुक्त और कई महावाणिज्यदूत मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आरिफ खत्री, जो 15 वर्षों से इस कला में सक्रिय हैं, ने बाग प्रिंटिंग को आधुनिक डिजाइनों और तकनीकों से जोड़ते हुए इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्हें 2021 में यूनेस्को एवं विश्व शिल्प परिषद द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, स्पेन सहित कई देशों में बाग प्रिंट का प्रदर्शन कर भारत और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है।



कल्लालगर मंदिर, तमिलनाडु

कल्लालगर मंदिर (कल्लालगर मंदिर) दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के मुदुरै जिले के एक गांव अलागर कोयिल में विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। वास्तुकला की दृष्टि से शैली में निर्मित, मंदिर को 6ठी-9वीं शताब्दी ईस्वी के अलवर संतों के प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिल सिद्धांत, नालयिरा दिव्य प्रबंधम में महिमामंडित किया गया है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देसमों में से एक है, जिन्हें कल्लालगर के रूप में पूजा जाता है, और उनकी पत्नी लक्ष्मी को थिरुमल्ल के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को संगम साहित्य में थिरुमालिरुंचोलाई और तमिल अलवर संतों द्वारा गाया गया नालयिरा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है।

मंडला में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दो महिला नक्सली ढेर

दोनों पर 14-14 लाख का इनाम था; एक एसएलआर और एक भरमार बंदूक मिली

मंडला (नप्र)। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, इसमें दो महिला नक्सली मारी गई हैं। मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 6 बजे बिछिया थाना क्षेत्र के मुंडिदादर और गन्हेरिदादर के जंगल में हुई। सचिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर, एक भरमार बंदूक, बायरलेस सेट और दैनिक जरूरत का सामान मिला है। पुलिस के मुताबिक, मारी गई नक्सलियों में से एक छत्तीसगढ़ और दूसरी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले की रहने वाली है। दोनों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

मध्यप्रदेश को अतिवाद मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती को नक्सल गतिविधियों से मुक्त करने के लिए राज्य पुलिस बल का अभियान तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि मंडला जिले में नक्सली कार्यों में सलिलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में हमारे हॉकफोर्स के जवानों ने 14-14 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सली को मार गिराया है। मृतक नक्सली की शिनाख्त प्रतिमा और ममता नाम से हुई है।

राजगढ़ में खेत में अचानक लगी आग

8 बीघा में लगी गेहूं की फसल जली; जानबूझकर आग लगाने का आरोप



राजगढ़ (भोपाल) (नप्र)। राजगढ़ के छतरपुरा गांव में मंगलवार रात को किसान यलकार सिंह के खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही पूरी फसल जलकर राख हो गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग दुर्घटनावश लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में किसी शादी के झगड़े के चलते आगजनी की आशंका जताई है।

लाखों रुपए की फसल जली, प्रशासन से मांगी मदद: किसान यलकार सिंह ने बताया कि इस घटना में करीब 8 बीघा गेहूं की कटकर रखी फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेहनत से उगाई गई फसल राख होने से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस आगजनी की जांच कराने और प्रभावित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है और घटना की छानबीन जारी है।

दो साल के बेटे के साथ

मां ने सुसाइड किया

●पति से विवाद के बाद पहले बेटे को फांसी लगाई, फिर खुद फंदे से झूली



गुना (नप्र)। गुना में एक महिला ने दो साल के बेटे की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। उसने पहले बेटे को फांसी से लटकवाया। फिर खुद फंदे से झूल गई। परिजन का आरोप है कि ससुराल वालों ने बेटे की हत्या की है। मामला राधौगढ़ के रामपुरा का है। जानकारी के मुताबिक, 24 साल की शिवानी की शादी रामेश्वर लोधा से हुई थी। उनका दो साल का बेटा शिवाय था। रामेश्वर शराब पीने का आदी था और नशे में पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। मंगलवार रात भी पति-पत्नी में विवाद हुआ। इसके बाद शिवानी अपने कमरे में चली गई और बेटे के साथ फांसी लगा ली। रात करीब 10 बजे ससुराल वालों ने कमरे में देखा तो मां-बेटे फंदे से लटक मिले। उनका कहना है कि शिवानी का शरीर हल्का गर्म था, इसलिए तुरंत जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया।

म.प्र.को 4303 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात

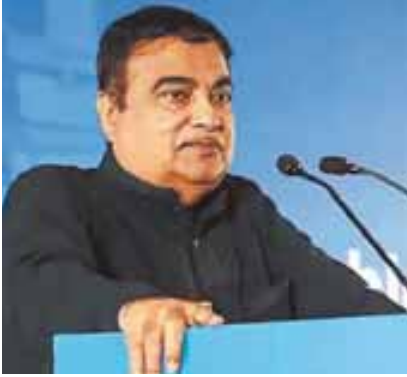
संदलपुर-नसरुल्लागंज बाईपास भी लिस्ट में, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक्स पर दी जानकारी

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने भोपाल जिले में संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास और भोपाल-कानपुर कॉरिडोर में विदिशा-सागर सहित प्रदेश में कुल चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिए स्वीकृत की गई 4303 करोड़ रुपए की नई सड़कों के बारे में बुधवार को जानकारी दी।

इन चार प्रोजेक्ट के जरिए बाईपास के रूप में एमपी में 102 किमी सड़कों का निर्माण होगा। सागर शहर में लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। यहां 4 लेन ग्रीन फील्ड बायपास बनाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के लिए मंजूर चार प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। इसमें मुरैना-ग्वालियर, सागर, भोपाल-सीहोर और विदिशा-सागर रोड पर बायपास बनाने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। यहां कुल 102 किमी सड़कों का निर्माण होगा, जिस पर 4302.93 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

भोपाल के संदलपुर नसरुल्लागंज बायपास के लिए 1535.66 करोड़

भोपाल जिले में संदलपुर से नसरुल्लागंज बाईपास तक 1535.66 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-146 बी के 43.200 किमी लंबाई के सेक्शन को 4-लेन बनाने के लिए साथ स्वीकृति दी गई है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-47, राष्ट्रीय राजमार्ग-46 और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 इन तीन राजमार्गों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके बनने से अत्यधिक भीड़भाड़ वाले पार्ट को पेन्ड शोल्डर सहित 4-लेन तक चौड़ा करने से



लंबे मार्ग के ट्रैफिक और माल ढुलाई की स्थिति में सुधार होगा। जिससे सुरक्षित आवाजाही और यात्रा के समय में कमी आएगी।

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर में विदिशा-सागर की सड़कें बनेंगी

एक अन्य ट्वीट में गडकरी ने कहा है कि इसी तरह प्रदेश के विदिशा और सागर जिले में राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक राष्ट्रीय

राजमार्ग-146 के 10.079 किमी हिस्से को 4-लेन बनाने के लिए 731.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह परियोजना राहतगढ़ के घनी आबादी वाले शहर को बाईपास करेगी और निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी बनाएगी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और राष्ट्रीय राजमार्ग-346 को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

4-लेन ग्रीनफील्ड बाईपास बदलेगा सागर शहर की तस्वीर

सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर लहदरा गांव जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बेरखेड़ी गुरु गांव जंक्शन तक ग्रीनफील्ड 4-लेन बाईपास बनेगा। 688.31 करोड़ रुपए की लागत से सागर पश्चिमी बाईपास (लंबाई: 20.193 किमी) का निर्माण होगा। मौजूदा राष्ट्रीय

राजमार्ग-146 शहरी बस्तियों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। जिसके कारण अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सागर जिले में लहदरा गांव जंक्शन को मंजूरी की जानकारी दी।

मुद्रेना और ग्वालियर के लिए एक्सेस कंट्रोल 4 लेन बायपास

ग्वालियर शहर के पश्चिमी हिस्से में 1347.6 करोड़ रुपए की लागत के 28.516 किमी लंबे एक्सेस कंट्रोल 4-लेन बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना मुरैना और ग्वालियर जिले तथा मार्ग में स्थित अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉकों और तहसील मुख्यालयों को जोड़ेगी। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-44, 46 और आगरा-ग्वालियर एक्सेस कंट्रोल हाईवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके विकास से लंबे मार्ग के यातायात और माल ढुलाई की स्थिति में सुधार होगा। जिससे यात्रा समय में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी का जताया आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को 4 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को सड़क अधोसंरचना निर्माण और क्षेत्रीय विकास में एक बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मध्यप्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 4302.93 करोड़ रुपये है। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर मध्यप्रदेश को मंजूर की गई इन परियोजनाओं की जानकारी साझा की है।



पन्ना में पति हाथ जोड़ता रहा, पत्नी उसे चांटे मारती रही...हिडन कैमरा लगाकर रिकॉर्ड की करतूत

पन्ना (नप्र)। पन्ना के अजयगढ़ निवासी लोकेश कुमार मांझी ने पन्ना पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत आवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्नी उनके साथ मारपीट करती है और ससुराल के लोग लगातार रुपये की मांग कर रहे हैं।

मामला सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अपनी पत्नी से लंबे समय से प्रताड़ित पति ने पत्नी के द्वारा की जाने वाली मारपीट के संबंध में साक्ष्यों को जोड़ने के लिए अपने कमरे में एक छुप्टा हुआ कैमरा लगाया और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सारे सबूत पन्ना पुलिस अधीक्षक को दिए। वीडियो में साफ तौर से उसकी पत्नी एवं सास के द्वारा बेरहमी से पति के साथ मारपीट की जा रही है और पति हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। युवक ने एक्सपी से की गई शिकायत में लिखा है कि उसकी शादी हर्षित रैकवार के साथ जून



शरीर में कई जगह चोटें आईं

युवक का कहना है कि मेरे घर में कमाने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। घरवालों की कोई भी मदद करने पर मेरी पत्नी मारपीट करती है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसका कहना है मेरे साथ लड़ाई करने के बाद पत्नी ने अपनी मां और भाई को बुलाया फिर 20 मार्च को सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इससे उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं। उसने थाना अजयगढ़ में भी आवेदन पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यह आवेदन देने की नौबत आई है। आवेदन के पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

2023 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी।

शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे: शादी के बाद से उनकी पत्नी, सास व साला रुपये और सोने-चांदी की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। लोकेश कुमार का कहना है कि उसकी बहन भी शादी लायक है। पत्नी माता-पिता की कोई मदद नहीं करने देती।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई

हलालपुर के 7 मैरिज गार्डन को नोटिस, नमकीन फैक्ट्री को बंद करने का आदेश

भोपाल (नप्र)। मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने काली परेड एरिया में स्थित कुंदन नमकीन फैक्ट्री को वायु प्रदूषण फैलाने पर बंद करने का आदेश दिया है। इस इलाके की दो अन्य फैक्ट्रियों को भी तीन दिन के अंदर सुधारात्मक कदम उठाने का नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही हलालपुर इलाके के सात मैरिज गार्डन को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन गार्डनों का सीवेज बड़े तालाब में मिल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल डायरेक्टर बुजेश शर्मा ने बताया कि हलालपुर क्षेत्र में चल रहे 7 मैरिज गार्डनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस भेजे गए गार्डनों में लॉयन सिटी मैरिज गार्डन, गुलशन एंड स्वागत मैरिज गार्डन, सनसिटी गुड गार्डन, ग्रीन सिटी गार्डन, मून लाईट गार्डन, लैंडमार्क गार्डन और सुंदरवन मैरिज लॉन शामिल

हैं। बोर्ड का कहना है कि ये गार्डन दूषित जल का उचित उपचार नहीं कर रहे और ठोस कचरे का निस्तारण भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे। ये गार्डन बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में स्थित हैं, जिससे जलस्रोतों पर खतरा बढ़ सकता है।

काली परेड एरिया में नमकीन फैक्ट्रियों से प्रदूषण की शिकायत पर कार्रवाई: 1 अप्रैल को काली परेड एरिया से नमकीन फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। निरीक्षण में कुंदन नमकीन फैक्ट्री से दूषित पानी बहाने के साथ वायु प्रदूषण भी पाया गया।

इस फैक्ट्री में ईटीपी अपग्रेड नहीं था। इसके अलावा, हरीश नमकीन और राकेश नमकीन फैक्ट्री को भी वायु प्रदूषण फैलाने पर नोटिस जारी किया गया है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में महिला की मौत, ग्रामीणों में दहशत

महुआ बीनने के लिए गई थी महिला, तभी बाघ ने हमला कर दिया

उमरिया (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पंपदा रेंज अंतर्गत कुशवाहा कोठिया गांव के पास बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। सुबह 9 हुई इस घटना के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए हैं। बताया गया है कि बाघ ने उस समय महिला पर हमला किया जब वह महुआ बीन रही थी। बाघ के हमले में मरने वाली महिला का नाम रानी सिंह पति ओमप्रकाश सिंह गोड़ उम्र 27 साल निवासी कुशमाहा कोठिया बताया गया है। घटना के समय महिला घर के बगल में सुबह 9 बजे महुआ बीन रही थी। इसी दौरान अचानक बाघ ने हमला कर दिया जिससे महिला की मौत हो गई।



गांव के नजदीक घूम रहा है बाघ

बताया गया है कि जंगल के बीच बसे इस

गांव के काफी नजदीक बाघ घूम रहा है। बाघ झाड़ियों में छिपा हुआ था और उसकी नजर आसपास थी। जब रानी महुआ बीनने के लिए झुकी तो बाघ ने उसे भी जानवर समझ लिया और उसके ऊपर हमला कर दिया। बाघ ने



महिला की गर्दन दबोच ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला को चीखने चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने महिला पर बाघ को हमला करते हुए देख लिया था,

जिससे उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बाघ महिला को मारने के बाद वहां से भाग गया।

ग्रामीणों में दहशत

गांव के इतने नजदीक बाघ के होने की वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से सुरक्षा की व्यवस्था करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि बाघ को यहां से हटाय जाए अन्यथा वह फिर किसी पर हमला कर सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि इन दिनों महुआ फिर रहा है और ग्रामीण महुआ बीनने जा रहे हैं। क्योंकि वे वनोपज पर वह निर्भर हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया है कि वह जंगल के ज्यादा अंदर ना जाएं साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए बाघ को जंगल के अंदर हॉकने का आश्वासन भी दिया है।

तीन दिन में 100 से ज्यादा कौओं की मौत

शहडोल पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुटी, कारण अभी अज्ञात

शहडोल (नप्र)।

शहडोल जिले में पिछले तीन दिनों से कौओं की मौत का सिलसिला जारी है। डीक बिजुरी के मैरटोला करौदी क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक कौओं की मौत हो चुकी है। वेटरनरी डिपार्टमेंट के उप संचालक डॉ. पीके पाठक ने विशेषज्ञ टीम को मौके पर भेजा है। टीम कौओं की मौत के कारणों की जांच कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, मौत के पीछे विषाक्त पदार्थों का सेवन, संक्रामक रोग या पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं।

निवासी बोले- कौओं की मौत चिंताजनक

स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले क्षेत्र में कौओं की संख्या में कमी देखी। राधेश्याम तिवारी ने कहा कि कौए पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतनी बड़ी संख्या में उनकी मौत चिंताजनक है। डॉ. पाठक ने कहा कि अगर यह किसी संक्रामक रोग का मामला है, तो अन्य पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में तेजी ला रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है।

